



## Press Release

### **May Day: Celebrating a membership of almost 4000 informal sector workers and 1679 registration in state workers' welfare board**

On the Maharashtra Day and International Workers' Day, Kamgar Sanrakshan Sammaan Sangh (KSSS) take pride in announcing its membership of close to 4000 informal sector workers since December 2021 after it undertook awareness campaign among construction workers in Mumbai. As a result of the awareness campaign, 1030 construction workers registered under the Maharashtra Building and other Construction Workers Board (MBoCW). Each registered construction worker and his/her family is eligible for schemes related to housing, health, education, insurance, maternity benefits etc. ranging from Rs. 2,00,000 to Rs. 35,00,000. KSSS has reached out to tens of thousands of workers in the process of awareness campaign for construction workers in Mumbai. KSSS has also undertaken the registration of 749 domestic workers. In addition to this, we have also facilitated the registration of tens of thousands of informal sector workers in the E-shram portal after the various labour authorities reached out to us in Mumbai. The focus of the union has been so far in Mumbai Metropolitan Region but soon it plans to expand its work in other districts and states.

Today is undoubtedly the day to celebrate our relentless work done since December 2021 but we still have miles to cover. In Maharashtra, a state with approx. 5cr informal sector workers, only few lakhs workers are registered under the various welfare/social security board. The state still needs more welfare boards to cover app-based workers, recycling workers, home based workers, garment industry and other informally employed workers.

Today, is also a time to take a moment and remember the lost lives and hardship faced by poor migrant/informal sector workers caused due the unplanned national COVID-19 lockdown. It is also time to examine what measures the government has taken to uplift India's 97% informal sector workforce and ensure that migrant worker crisis like situations do not repeat in future.

At the same time, we cannot ignore the state-sponsored communal atmosphere today which is designed to distract from the real issues faced by the people, whether labor related, governance related or inflation related. This needs to be properly responded and dealt with, through collective and united efforts, to bring the focus back to people's rights and struggles. We also have to understand and fight poverty and denial of rights caused due to increasing discrimination whether it is based on caste, religion, gender, regionalism or any other forms of prejudice, bias and stigma faced by the citizens. With this in mind, KSSS today resolve to further strengthen its mobilising and unionising work to ensure that our informal sector work force not only get all the social security benefits like housing, health, education, pension and other benefits but also due recognition, rights and dignity!

We also take this opportunity to appeal to trade unions and other like-minded organisations and individual to take part in the larger consultation on the social security agenda for the informal sector workers in Maharashtra. A meeting has been organized in this regard on 10<sup>th</sup> of May in Aurangabad. Details given in the poster attached with this statement.

Zindabad!

Bilal Khan Anita Dhole Jameela Begum Uday Mohite Akhilesh Rao Umar Shaikh Akhtari Begum

**Place: Mumbai**

**Date: 1<sup>st</sup> May 2022**



### प्रेस विज्ञप्ति

**मई दिवस: लगभग 4000 असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की सदस्यता और राज्य श्रमिक कल्याण बोर्ड में 1679 पंजीकरण करने के बाद आज खुशी मानने का दिन है।**

महाराष्ट्र दिवस और अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस पर, कामगार संरक्षण सम्मान संघ (केएसएसएस/कस्स) ने दिसंबर 2021 से मुंबई में निर्माण मजदूरों के बीच जागरूकता अभियान चलाने के बाद से लगभग 4000 अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों की अपनी यूनियन में सदस्यता की घोषणा करते हुए गर्व महसूस कर रहा है। जागरूकता अभियान के परिणामस्वरूप, महाराष्ट्र भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड (MBoCW) के तहत 1030 निर्माण श्रमिकों को पंजीकृत किया गया। प्रत्येक पंजीकृत निर्माण श्रमिक और उसका परिवार आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, बीमा, मातृत्व लाभ आदि से संबंधित योजनाओं के लिए पात्र है जिसके फायदे रु. 2,00,000 से रु. 35,00,000 के बीच के होते हैं। कस्स मुंबई में निर्माण श्रमिकों के लिए जागरूकता अभियान की प्रक्रिया से कई हजारों श्रमिकों तक पहुंच गया है। कस्स ने 749 घरेलू कामगारों का पंजीकरण भी किया है। इसके अलावा, हमने मुंबई में विभिन्न श्रम अधिकारियों के हमारे पास पहुंचने के बाद ई-श्रम पोर्टल में हजारों अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों के पंजीकरण की सुविधा भी प्रदान की है। यूनियन का ध्यान अब तक मुंबई महानगर क्षेत्र में रहा है लेकिन जल्द ही यह अन्य जिलों और राज्यों में अपने काम का विस्तार करने की योजना बना रही है।

आज निस्संदेह दिसंबर 2021 से निरंतर प्रयास के तहत हुए हमारे काम का जश्न मनाने का दिन है, लेकिन अभी तो यह शुरुवात है आगे और भी चुनौतियाँ हैं। महाराष्ट्र में, लगभग 5 करोड़ अनौपचारिक रूप से काम करने वाले कामगार हैं, परन्तु इसमें से केवल कुछ लाख श्रमिक विभिन्न कल्याण / सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के तहत पंजीकृत हैं। महाराष्ट्र को अभी भी अन्य असंगठित कामगार जैसे की ऐप-आधारित कामगार, recycling क्षेत्र के कामगार, घर में बैठ कर काम करने वाले कामगार, परिधान उद्योग और अन्य अनौपचारिक रूप से काम करने वाले कामगारों के लिए अधिक कल्याण बोर्डों की आवश्यकता है जिससे उनकी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

आज के दिन हमे उन गरीब प्रवासी/असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को याद करने की भी ज़रूरत है जिन्होंने अनियोजित रूप से थोपे गए COVID-19 राष्ट्रीय लॉकडाउन के चलते अपनी जाने गवाई व अन्यो ने अपार कठिनाई का सामना किया। यह जांचने का भी समय है कि सरकार ने भारत के 97% असंगठित क्षेत्र के कार्यबल के उत्थान के लिए क्या उपाय किए हैं? यह भी देखना होगा की क्या सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि lockdown के दौरान हुए प्रवासी कामगार संकट जैसी स्थिति भविष्य में ना दोहराई जाए? हमे इसके साथ साथ आज राज्य नियोजित सांप्रदायिक माहौल को भी नज़रअंदाज़ नहीं कर सकते जोकि असल मुद्दे चाहे वो कामगार सम्बंधित हों या शासन करने सम्बंधित या महगाई से सम्बंधित हों, उस सब से भटकाने के लिए बनाया गया है। लोगों के अधिकारों और संघर्षों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सामूहिक और एकजुट प्रयासों के माध्यम से इसका उचित जवाब दिया जाना चाहिए और इससे निपटा जाना चाहिए। हमे बढ़ते भेदभाव चाहें वो जाती, लिंग, क्षेत्रवाद पर आधारित या अन्य रूप में हो, हमे हर प्रकार के भेद-भाव से हो रही गरीबी को भी समझना होगा और लड़ना होगा। इस सब को ध्यान में रखते हुए, केएसएसएस आज संकल्प लेता है की मजदूरों को संगठित करने का कार्य और मज़बूत करेगा। यह कार्य के जरिये ऐसा सुनिश्चित किया जायेगा कि हमारे असंगठित क्षेत्र के कार्य बल को न केवल आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेंशन और अन्य लाभ जैसे सभी सामाजिक सुरक्षा लाभ मिलते हैं, बल्कि उचित मान्यता, अधिकार और सम्मान भी मिले!

हम इस अवसर पर हम ट्रेड यूनियनों और अन्य समान विचारधारा वाले संगठनों और व्यक्तियों से महाराष्ट्र में अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा एजेंडे पर बड़े परामर्श में भाग लेने की अपील करते हैं। इस संबंध में 10 मई को औरंगाबाद में एक बैठक आयोजित की गई है। विवरण इस स्टेटमेंट के साथ संलग्न पोस्टर में दिया गया है।

जिंदाबाद!

बिलाल खान अनीता ढोले जमीला बेगम उदय मोहिते अखिलेश राव उमर शेख अख्तरी बेगम

**मुंबई। दिनांक: १ मई २०२२**